RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 23 MARCH 2022 TO 29 MARCH 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 29 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कच्चे तेल की ऊंची कीमत के लिए वह जिम्मेदार नहीं- सऊदी अरब

Page 2

शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक को हाइड्रोजन में बदलने की विधि विकसित की

Page 4

अदाणी पोर्ट्स का कार्गो वॉल्यूम बढ़कर 30 करोड़ मीट्रिक टन हुआ

Page 7

editoria!

तकनीक सीखें अधिकारी

जीवन के हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक और संबंधित नये रूपों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में नीतियों को सही ढंग से लागू करने तथा सरकारी सेवाओं को आमजन के लिए सुलभ बनाने के लिए आवश्यक है कि देश के बड़े अधिकारी ऐसी तकनीकों को जानें व सीखें. इस आवश्यकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डाटा भविष्य में एक बड़ी ताकत होने की कगार पर है. डाटा गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के महत्व पर देते हुए उन्होंने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से आग्रह किया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देनेवाले इस संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की प्रयोगशाला स्थापित किया जाये. प्रधानमंत्री मोदी की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारी दस्तावेजों के आंकड़े केवल संख्या भर नहीं होते, बल्कि उनमें सपनों, आकांक्षाओं और चुनौतियों का जीवन धड़कता है. यदि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में गति आती है और उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, तो इससे देश का तीव्र विकास संभव हो सकता है. जिले से लेकर केंद्र व राज्य सरकारों के शीर्ष विभागों तथा उपक्रमों के संचालन का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों पर ही होता है. डाटा प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के बारे में जानकारी लेकर वे अपने दायित्व का प्रभावपूर्ण निर्वाह कर सकते हैं. कई ऐसे ठोस शोध उपलब्ध हैं, जो बताते हैं कि आगामी समय में हमारे जीने, काम करने और एक-दूसरे से जुड़ने की सारी प्रक्रियाओं में आमूल-चूल बदलाव होगा। भले ही हम अत्याधुनिक तकनीक संभावना एवं क्षमता से परिचित हों या नहीं हो, समाज और धरती के लिए इसके अनगिनत लाभ हैं. यदि हमारे अधिकारी तकनीक से परिचित होंगे, तो वे इसके लाभ भी सुनिश्चित कर सकेंगे और इसकी खामियों को भी दूर कर पायेंगे. डिजिटल तकनीक के विस्तार की रफ्तार का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का वैश्विक बाजार 190 अरब डॉलर तक हो जायेगा तथा 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में इस तकनीक का योगदान 15.7 ट्रिलियन डॉलर तक संभावित है. प्रशासनिक क्षेत्र में इसकी साक्षरता जरूरी है क्योंकि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख स्थान रखता है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस ओर ध्यान दिलाकर सराहनीय पहल की है. इस संबंध में देरी करना नुकसानदेह हो सकता है. हमारा देश डिजिटल तकनीक में अगली पंक्ति के देशों में शामिल है. हमारे सॉफ्टवेयर उद्योग के पास वर्षों का अनुभव है तथा बड़ी संख्या में स्टार्टअप कंपनियां भी आ रही हैं. इस उपलब्धता का लाभ उठाकर सरकारी अधिकारी शासन प्रक्रिया में नयी तकनीकों का उपयोग बढ़ाने के साथ डाटा सुरक्षा को भी पुख्ता कर सकेंगे. आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात का संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारें तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देंगी.

2 दिन में 1.60 बढ़ गए पेट्रोल के दाम

थोड़ा दिल मजबूत कीजिए अभी 14.40 रुपये बाकी हैं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई। 137 दिन के विराम के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने ही पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी की थी। यह बुधवार को भी जारी रहा। पेट्रोल की कीमतों में जहां 80 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हुई वहीं डीजल भी 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली के पेट्रो ल पंप पर बुधवार को पेट्रोल की कीमत जहां 97.01 रुपये प्रति लीटर पर पहंच गई, वहीं डीजल भी 88.27 रुपये पर चला गया। जानकारों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कई दिनों तक इजाफा हो सकता है।

अभी कितनी बढ़ सकती है कीमत

पेट्रोल और डीजल की कीमत में दो दिन में प्रति लीटर 1.60 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल-डीजल की कीमत में जब आखिरी बार बदलाव हुआ था तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत करीब 82 डॉलर प्रति बैरल थी जो अभी 116 डॉलर के आसपास है। इस हिसाब से देखें तो देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में 14.40 रुपये का इजाफा हो सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें तेजी आई। एक वक्त तो यह 139 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया था जो 2008 के बाद इसका उच्चतम स्तर था। बीच में यह 100 डॉलर के नीचे आ गया था। लेकिन अमेरिका के बाद अब यूरोपीय देश भी रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इससे तेल की कीमतों में फिर उछाल आई है और यह अभी 116 डॉलर के आसपास है।

पिछले साल सितंबर में 8.15 रुपये महंगा हुआ था पेट्रोल

पिछले साल नवंबर से पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों के चुना व के बाद पिछले साल सितंबर के अंतिम दिनों से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुईं, वह दिवाली से पहले तक जारी रही। इतने दिना में ही पेट्रोल 8.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कुछ कटौती की थी। हालांकि बीते साल सात नवंबर से इसके दाम स्थिर हैं।

पिछले साल 9.45 रुपये महंगा हुआ था डीजल

पिछले साल सितंबर के बाद पेट्रोल के मुकाबले डीजल का बाजार ज्यादा तेज हुआ था। कारोबारी लिहाज से देखें तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल बनाना महंगा पड़ता है। लेकिन भारत के खुले बाजार में पेट्रोल महंगा बिकता है और डीजल सस्ता बिकता है। बीते साल 24 सितंबर से यहां जो डीजल में आग लगनी शुरू हुई थी वह उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद रुकी थी। 24 सितंबर 22 से दिवाली तक डीजल करीब 9.45 रुपये महंगा हो गया था।

डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे की मजबूती के साथ खुला

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक रुझान के अनुरूप बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की मजबूती के साथ 75.99 रुपया प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 76.08 के भाव पर खुला और जल्द ही मजबूती पकड़ते हुए 75.99 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर पहुंच गया। इस तरह शुरुआती कारोबार में रुपये ने पिछले दिवस की तुलना में 19 पैसे की बढ़त दर्ज की। मंगलवार को रुपया 76.18 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर स्थिर रुख के साथ बंद हुआ था। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि बुधवार को रुपया मजबूती के साथ खुला जिसमें कच्चे तेल में आई नरमी की भी भूमिका है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से मजबूती प्रभावित हो सकती है। अय्यर ने कहा कि एशिया और उभरते बाजारों में बुधवार को देखी गई शुरुआती बढ़त से रुपये को लेकर कारोबारियों की धारणा बेहतर हो सकती है। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.47 पर रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.54 प्रतिशत बढ़कर 117.26 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

9 महीने में ही पेट्रोल-डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स से

केंद्र सरकार ने कमाए 3.31 लाख करोड़

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मौजूदा वित्त वर्ष (2021-22) के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 24 फीसद बढ़कर 3,31,621.07 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। नीमच के सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने मंगलवार को बताया कि सूचना के अधिकार कानून के तहत दायर उनकी अर्जी पर केंद्र के दो विभागों ने उन्हें यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि यह जानकारी ऐसे वक्त सामने आई है, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, वहीं घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। गौड़ ने आरटीआई कानून के तहत मिले ब्योरे के हवाले से बताया कि भारत में अप्रैल से दिसंबर, 2021 के बीच पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 37,653.14 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क वसूला गया, जबकि देश में इन पदार्थों के विनिर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 2,93,967.93 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा हुए। आरटीआई कानून से मिली जानकारी के मुताबिक, कोविड-19 के भीषण प्रकोप वाले पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के बीच पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली क्रमशः 25,025.33 करोड़ रुपये और 2,42,089.89 करोड़ रुपये के स्तर पर रही थी। यानी दोनों करों की मद में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में इन उत्पादों पर कुल 2,67,115.22 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था।

रूस से सस्ता क्रूड ऑइल खरीदने को भारतीय कंपनियों में मची होड़

नई दिल्ली। एजेंसी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. ने रूस से 20 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की है। भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां कम दाम पर उपलब्ध रूसी तेल खरीदने को लेकर कदम उठा रही हैं। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि आईओसी की तरह एचपीसीएल ने भी यूरोपीय कारोबारी विटोल के जरिये रूसी यूराल्स क्रूड (रूस के निर्यात स्तर के कच्चे तेल) की खरीद की है। इसके अलावा मेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. ने इसी प्रकार का 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने को लेकर निविदा जारी की है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पश्चिमी देशों की उस पर विभिन्न पाबंदियों के चलते कई कंपनियां और देश रूसी तेल खरीदने से बच रहे हैं। इससे रूसी कच्चे तेल का दाम कम हुआ है और यह बाजार में भारी छूट पर उपलब्ध है।

भारतीय रिफाइनरी कंपनियां जारी कर रहीं निविदाएं

इस अवसर का लाभ उठाने के इरादे से भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने कम दाम पर तेल खरीदने को लेकर निविदाएं जारी की हैं। इन निविदाओं के लिये वे कारोबारी सफल बोलीदाता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने सस्ते रूसी तेल का भंडार रखा हुआ है। सूत्रों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी आईओसी ने पिछले सप्ताह विटोल के जरिये मई डिलिवरी के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद की। कंपनी को यह तेल 20 से 25 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिला। इसके बाद इस सप्ताह एचपीसीएल ने 20 लाख बैरल यूराल्स क्रूड की खरीद की है।

रूसी तेल खरीदने से बच सकती है रिलायंस

इस बीच, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का परिचालन करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. रूसी ईंधन खरीदने से बच सकती है। इसका कारण कंपनी का अमेरिका में निवेश है। ऐसे में रूस पर पाबंदी से उसके कारोबार पर असर पड़ सकता है।

आईओसी का साल 2020 से है समझौता

आईओसी का साल 2020 से रूस के रोसनेफ्ट से कच्चा तेल खरीदने का समझौता है। लेकिन, समझौते के तहत इसने शायद ही कभी आयात किया, क्योंकि रूस से तेल के परिवहन की लागत इसे आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बना देती है। सूत्रों ने कहा कि प्रति बैरल 20 से 25 डॉलर की छूट ने माहौल रूसी कच्चे तेल के पक्ष में बना दिया है और भारतीय रिफाइनरी कंपनियां इस अवसर को हाथों-हाथ ले रही हैं।

कंपनियां अपनी शर्तों पर कर रही खरीद

सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन की अनुषंगी एमआरपीएल ने भी मई डिलीवरी के लिये 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की इच्छा जतायी है। कंपनियां अपनी शर्तों के आधार पर रूस से कच्चे तेल की खरीद कर रही हैं। इसमें विक्रेता के भारतीय तट तक कच्चे तेल की आपूर्ति शामिल है। यह शर्त माल ढुलाई और बीमा की व्यवस्था में प्रतिबंधों के कारण होने वाली किसी भी जटिलता से बचने के लिए रखी गई है। सूत्रों ने कहा कि रूस के साथ व्यापार का निपटारा डॉलर में किया जा रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था को अब तक पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है।

Bank Strike

जल्द निपटा लें जरूरी काम, एक हफ्ते में लगातार चार दिन बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम हो तो जल्द निपटा लें क्योंकि इसी महीने यानी मार्च के बचे एक सप्ताह में लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे। इसकी प्रमुख विभिन्न कर्मचारी संगठनों की हड़ताल है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने यह जानकारी दी है। बैंक यूनियन की हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, बैंक यूनियन ने 28 और 29 मार्च (सोमवार और मंगलवार) को हड़ताल की घोषणा की है। इससे पहले शनिवार और रविवार को बैंक में छुट्टी रहेगी। इसका मतलब है कि इस महीने चार दिन बैंकों के कामकाज पर असर देखने को मिल सकता है।

देशव्यापी हड़ताल में ये होंगे शामिल

एसबीआई ने भारतीय बैंक संघ (IBA) के हवाले से बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बैंक कानून संशोधन विधेयक-2021 के विरोध में बैंक यूनियन की ओर से 28 और 29 मार्च को दो दिवसीय हड़ताल बुलाई गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने नोटिस देकर देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसले के बारे में जानकारी दी है।

रूस से अब तक किस-किस देश ने तेल खरीदना बंद किया?

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी तेल खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन यूरोपीय संघ के सदस्य रूसी तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाने के मामले में एक राय नहीं बना पा रहा हैं। दरअसल, यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री सोमवार को रूसी गैस और तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सहमत नहीं हो सके क्योंकि यूरोपीय संघ अपनी जरूरत की 40% गैस और 27% तेल के लिए रूस पर निर्भर करता है। यूरोपीय संघ के देशों के अलावा भी कई देश हैं, जो अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं. तो चलिए सबसे पहले उन देशों के बारे में जानते हैं, जो रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और फिर उन देशों के बारे में जानेंगे, जो अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं।

इन देशों की रूसी तेल खरीद पर रोक

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन, रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा चुके है। विस्तार से बताएं तो ब्रिटिश तेल प्रमुख कंपनी बीपी रोसनेफ्ट में अपनी हिस्सेदारी छोड़ रहा है। वह रूसी बंदरगाहों पर लोडिंग के लिए रूसी संस्थाओं के साथ नए सौदे नहीं करेगा जब तक कि 'आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक' न हो। जापान के सबसे बड़ी रिफाइनर ENEOS ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है, जबकि पिछले समझौतों के तहत हस्ताक्षर किए गए कुछ कार्गो अप्रैल के आसपास जापान पहुंचेंगे। इसके अलावा ऊर्जा समूह ENI, जिसका 30.3% स्वामित्व इटली सरकार के पास है, उसने रूसी तेल की खरीद पर रोक लगा दी है।

जर्मनी की बायर्नोइल रिफाइनरी में किसी भी रूसी क्रूड का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें ENI और रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है। वहीं, नॉर्वे की ऊर्जा फर्म EQUINOR ने रूसी तेल का व्यापार बंद कर दिया है। पुर्तगाली तेल और गैस कंपनी GALP ने रूस या रूसी कंपनियों से पेट्रोलियम उत्पादों की सभी नई खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इनके अलावा फिनलैंड स्थित NESTE के पास वर्ष के अंत तक रूसी तेल अनुबंध हैं लेकिन वह कोई नया आपूर्ति समझौता नहीं कर रही है। सऊदी अरबपति मोहम्मद हुसैन अल-अमौदी के स्वामित्व वाली स्वीडन की सबसे बड़ी रिफाइनर ईईं ने रूसी कच्चे तेल के नए ऑर्डर को 'रोक दिया' है, जो इसकी खरीद का लगभग 7% हिस्सा है। स्पेन की कंपनी REPSOL ने हाजिर बाजार में रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम ट्रेडर SHELL रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगी और सभी रूसी हाइड्रोकार्बन में अपनी भागीदारी को समाप्त कर देगी। फ्रांसीसी तेल प्रमुख TOTALENERGIES इस साल के अंत तक रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदना बंद कर देगी और नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। स्विस रिफाइनर VARO ENERGY ने कहा कि उसकी रूसी क्रूड खरीदने के लिए नए सौदे करने की योजना नहीं है। यह जर्मनी की बायर्नोइल रिफाइनरी में 51.4% की मालिक है।

कौन-कौन रूस से खरीद रहे हैं तेल?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुल्गारिया, जर्मनी, ग्रीस, इटली, हंगरी, पोलैंड, नीदरलैंड, चीन, फ्रांस और भारत अभी भी रूसी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, इनमें से कई यूरोपीय संघ के देश रूसी तेल पर जल्द ही प्रतिबंध लगाने की योजना भी बना सकते हैं।

कच्चे तेल की ऊंची कीमत के लिए वह जिम्मेदार नहीं- सऊदी अरब

दुबई। एजेंसी

सऊदी अरब ने सोमवार को कहा कि वह यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति में कमी की "कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।" आमतौर पर नपे-तुले बयान देने वाले सऊदी अरब ने असामान्य रूप से कठोर चेतावनी दी है, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि उनकी छोटी-छोटी टिप्पणियां भी तेल की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं और वैश्विक बाजार में हलचल मचा सकती हैं।

हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल केंद्रों पर हमले किए हैं, जिससे युद्ध के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है, जो 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा यमन की राजधानी सना और उत्तरी हिस्सों पर कब्जा करने के बाद शुरू हुआ था। सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने हूति विद्रोहियों को हटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के लिए भीषण हवाई हमलों के साथ इस कार्रवाई का जवाब दिया। सात साल बाद यह संघर्ष एक खूनी गतिरोध में बदल गया और दुनिया में सबसे बड़े मानवीय संकट में से एक को जन्म दिया। सरकारी 'सऊदी प्रेस एजेंसी' ने सऊदी विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा कि देश "यह घोषणा करता है कि उसके तेल केंद्रों पर हमलों के मद्देनजर वैश्विक बाजार में अगर तेल की आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी आती है तो वह इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।" यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब उत्पादन सीमित करने वाले सौदे को लेकर ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ सऊदी अरब भी इस तरह की वार्ता कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र के तेल उत्पादकों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच तेल की कीमत घटाने में मदद करने के लिए अधिक कच्चा तेल निकालने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रस्ताव का अब तक विरोध किया है। सऊदी अरब ने एक बयान में कहा, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सऊदी अरब की तेल उत्पादन क्षमता और उसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में खलल डालने वाले हमलों को रोकने तथा ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने में निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।" यमन के ईरान समर्थित विद्रोहियों ने रविवार को सऊदी अरब के तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाकर हमले शुरू किए थे, जिससे देश के दूसरे सबसे बड़े शहर जिद्दा के बंदरगाह में एक पेट्रोलियम वितरण केंद्र में आग लग गई और लाल सागर तट पर यानबू में एक पेट्रोकेमिकल परिसर में उत्पादन बाधित हो गया।

ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बना नया वायरस पहुंचा भारत

इन राज्यों में मिले मरीज; जानें कितना है खतरनाक

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन इस बीच देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा (Delta) और ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट मिलकर बना है। डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना डेल्टाक्रॉन (Deltacron) वेरिएंट भारत पहुंच गया है और कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं।

देश के इन राज्यों में आए डेल्टाक्रॉन के मामले

तेलंगाना टुडे के हवाले से मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कोविड जीनोमिक्स कंसोर्सियम और GSAID ने इशारा किया है कि देश में 568 मामले जांच के दायरे में हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 221 मामलों में डेल्टाक्रॉन वेरिएंट के संकेत मिले हैं, जो हॉटस्पॉट बन गया है। इसके बाद तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, पश्चिम बंगाल में 32 और तेलंगाना में 25 और नई दिल्ली में 20 मामले जांच के दायरे में हैं।

डेल्टा और ओमिक्रॉन का हाइब्रिड वेरिएंट है डेल्टाक्रॉन

एक्सपर्ट्स की मानें तो ये एक सुपर सुपर-म्यूटेंट वायरस, जिसका वैज्ञानिक नाम BA.1 + B.1.617.2 है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना एक हाइब्रिड स्ट्रेन है, जिसे सबसे पहले साइप्रस के रिसर्चर्स ने पिछले महीने खोजा था। उस समय तो वैज्ञानिकों ने इसे लैब में हुई एक तकनीकी गलती समझा था। लेकिन अब इसके ब्रिटेन में केस सामने आ रहे हैं। डेल्टाक्रॉन (Deltacron) कोरोना वायरस का एक हाइब्रिड वेरिएंट है जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बनता है।

बढ़ती लागत की वजह से FMCG कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला

पैकेट्स साइज को 10% तक छोटा किया

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस और यूक्रेन में युद्ध का असर अब देश में दिखने लगा है। पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, रसोई गैस, दूध, रोजमर्रा के सामानों के दाम में इजाफा होने लगा है। यूक्रेन संकट से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर एफएमसीजी कंपनियों पर भी पड़ी है। क्रूड की कीमतों में तेजी से एफएमसीजी कंपनियों पर लागत का बोझ ज्यादा बढ़ा गया है। बढ़ती लागत की वजह से इश्ण्ड कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कंपनियों ने कई प्रोडक्ट्स के पैकेज के साइज घटा दिए है. इससे कंपनियों को बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर बीते छह महीनों से लगातार दाम बढ़ा रही है। कंपनी सर्फ साबुन के दाम 2 से 17 फीसदी तक बढ़ा दिए। बीते छह माह में उत्पादों के दाम 25 से 30 फीसदी तक बढ़ गए। 2 मिनट में बनने वाली मैगी 2 रुपए और महंगी हो गई। नया दाम 12 से बढ़कर 14 रुपए हो गया। पारले प्रोडक्ट्स कीमतों में 10-15 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। महंगाई के दबाव की वजह से कंज्यूमर्स ने अपना खर्च कम किया है। वे छोटे पैक खरीद रहे हैं। इसलिए कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और प्रोडक्ट्स के पैकेट साइज को घटा दिया है।

कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चा तेल, पॉम ऑयल और गेहूं तीनों कमोडिटी के दाम बेतहाशा बढ़े। यही तीन कमोडिटी एफएमसीजी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा कच्चा माल है। क्रूड की कीमतें बीते एक साल में 124 फीसद बढ़ीं। एफएमसीजी कंपनियों की लागत में करीब 10 से 15 फीसद की हिस्सेदारी पैकेजिंग की होती है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल क्रूड ऑयल की तर्ज पर महंगा होता है। यानी जितनी तेजी कच्चे तेल में उतना महंगा पैकेजिंग मैटेरियल। इसके अलावा बल्क डीजल और कोयला महंगा होने के बाद कंपनियों के लिए एनर्जी की लागत भी बढ़ी है।

पैकेट्स का साइज 10 फीसदी तक छोटा हुआ

कच्चे माले के महंगे होने से एफएमसीजी कंपनियों की लागत 20 से 30 फीसदी बढ़ गई है। कंपनिया छोटे पैकेट्स और एमआरपी (MRP) बढ़ाकर लागत के बोझ को डालने की कोशिश की है। प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के पैकेट छोटे किए गए और एमआरपी बढ़ाई गई।

इन कंपनियों के पैकेट्स हुए छोटे

जिन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के पैकेट के साइज छोटे किए हैं, उनमें पारले (Parle), ब्रिटानिया (Britannia), हल्दीराम (Haldiram), एचयूएल (HUL) शामिल हैं। पारले का बिस्कुट, ब्रिटानिया का मिल्क रस्क का पैकेट छोटा हुआ है। वहीं हल्दीराम का नमकीन और HUL का (Lifebuoy) साबुन भी छोटा हुआ है।

फिच ने भारत के जीडीपी अनुमान को घटाया

नई दिल्ली। एजेंसी

रेटिंग एजेंसी 'फिच' ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 10.3 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है।एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस के 'ओमीक्रोन' स्वरूप के प्रकोप में कमी आने के बाद से प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिससे इस साल जून की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि में तेजी लाने के लिए मंच तैयार हुआ है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास के अनुमान को 0.6 प्रतिशत बढ़ाकर 8.7 प्रतिशत कर दिया है। फिच' ने कहा, ''हालांकि, हमने भारत के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 में अपने विकास पूर्वानुमान को तेजी से बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण घटाकर 8.5 प्रतिशत (-1.8 फीसदी की कमी के साथ) कर दिया है।''

गैस सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट प्रक्रिया हुई सरल

बिना इंटरनेट के भी पूरा कर सकेंगे प्रोसेस

नयी दिल्ली। एजेंसी

पांच राज्यों में चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर उन ग्राहकों के लिए है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने बीते सप्ताह एक वॉयस बेस्ड पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है।

कैसे कर सकेंगे पेमेंट?

UltraCash Technologies ने अल्ट्राकैश नाम की एक मोबाइल पेमेंट एप्लिकेशन तैयार किया है। इसे नेशनल पेमेंट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अर्थोराइज्ड किया है। इसी आपसी सहयोग के जरिए भारत गैस के कस्टमर 080-4516-3554 नंबर पर कॉल करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। साथ ही इसके जरिए पेमेंट भी कर पाएंगे। बता दें, इसके लिए स्मार्ट फोन जरूरी नहीं है। एक सामान्य फोन के जरिए भी इसकी बुकिंग की जा सकती है।

सोने चांदी की कीमतें बढ़ी

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

नई दिल्ली। इंदौर सराफा व्यवसाई संतोष वाधवानी रत्न विशेषज्ञ ने बताया कि घरेलू बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी आई है। घरेलू बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में तेजी आई है। एमसीएक्स पर अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना मंगलवार सुबह 0.29 फीसदी करीब 151 रुपये की बढ़त के साथ ही 51,806 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं इसके अलावा जून की डिलीवरी वाला सोना इससमय 0.39 फीसदी तकरीबन 202 रुपये की तेजी के साथ ही 52,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर नजर आया। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी शुरुआती कारोबार में सोने की वायदा और हाजिर दोनों कीमतें बढ़ीं हैं। दूसरी ओर, चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में भी शुरुआती कारोबार में बढ़त आई है। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम में भी आज उछाल आया है।

सोने के साथ ही चांदी की वायदा कीमतों में भी शुरुआती कारोबार में बढ़त रही। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में 5 मई 2022 की डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 0.70 फीसद या 478 रुपये की तेजी के साथ 68,827 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखाई दी। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी के वायदा व हाजिर दोनों भाव बढ़त के साथ कारोबाबर करते दिखाई दिए। इसके अलावा क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमतें भी बढ़ी हैं।

News यू केन USE

रक्षा मंत्रालय ने 8357 करोड़ रुपये के सैन्य साजोसामान की खरीद को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 8,357 करोड़ रुपये के सैन्य संसाधन और मशीनरी की खरीद को मंजूरी दे दी, जिनमें वायु रक्षा गोलाबारी नियंत्रण रडार और जीसैट-7बी उपग्रह को खरीदना शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में खरीद प्रस्तावों को 'आवश्यकता की स्वीकृति' अनुमोदन दिया गया। बयान के मुताबिक, इन उपकरणों और प्रणालियों के अधिग्रहण से सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों में वृद्धि होगी और उन्हें बेहतर दृश्यता, बेहतर संचार मिलेगा तथा दुश्मन के विमानों का पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। 'आवश्यकता की स्वीकृति' को मंजूरी देने से निविदा प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा बलों की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को स्वदेशी तरीके से ही हासिल किया जाएगा।

विमान यात्रियों के लिए कोविड अंकुशों में ढील, चालक दल को पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं होगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी अंकुशों में ढील देते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए पीपीई किट पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 'मेडिकल इमरजेंसी' स्थिति के लिए तीन सीटों को खाली रखने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही हवाईअड्डे के सुरक्षाकर्मी अब यात्रियों की हाथ लगाकर सुरक्षा जांच कर सकेंगे। मंत्रालय के 21 मार्च के आदेश में कहा गया है कि ये अंकुश हवाई उड़ानों के सुगम परिचालन के लिए हटाए गए हैं। भारत का विमानन क्षेत्र ओमीक्रोन स्वरूप के मंद पड़ने के बाद पुनरुद्धार की राह पर है। फरवरी में घरेलू उड़ानों पर हवाई यात्रियों की संख्या 76.96 लाख रही, जो जनवरी से 20 प्रतिशत अधिक है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि 'मेडिकल इमरजेंसी' के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अब तीन सीटें खाली रखने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

मार्च-मई के दौरान होटल बुकिंग महामारी-पूर्व के स्तर को पार करेगी : आईएचसीएल

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में इस वर्ष मार्च से मई के दौरान होटल बुकिंग कोविड-19 महामारी के पूर्व के स्तर को पार कर सकती है। इंडियन होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएचसीएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत चटवाल ने मंगलवार को यह बात कही। टाटा समूह की आतिथ्य फर्म के प्रमुख ने कहा कि उद्योग का दीर्घकालिक दृष्टिकोण पांच से दस साल पहले की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक होने जा रहा है। उन्होंने कहा, "पिछले चार से छह सप्ताह में हम जो अनुभव कर रहे हैं वह बहुत मजबूत पुनरुद्धार है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मार्च, अप्रैल और मई में क्षेत्र का कारोबार 2019 की इसी अवधि की तुलना में अधिक होगा।" उन्होंने कहा कि उद्योग में पुनरुद्धार का मुख्य कारण घरेलू मांग है, क्योंकि बायो बबल के कारण सीमित संख्या में ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हो रहा है। चटवाल ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिर से शुरू होने में अभी समय है लेकिन घरेलू मांग बहुत ज्यादा मजबूत है।" उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर शुरू हो रही हैं।

शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक को हाइड्रोजन में बदलने की विधि विकसित की

मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने प्रकाश के संपर्क में प्लास्टिक को हाइड्रोजन में बदलने की विशेष विधि विकसित की है। प्लास्टिक से हाइड्रोजन बनना इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि हाइड्रोजन गैस भविष्य का सबसे व्यावहारिक गैर-प्रदूषक इंधन माना जाता है। प्लास्टिक अधिकतर पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं परंतु ये बायो-डिग्रेडेबल नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें आसानी से बिना नुकसान के अन्य उत्पादों में विघटित नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि अब तक बने 4.9 बिलियन टन प्लास्टिक का अधिकांश आखिर में लैंडफिल पहंचेगा जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़ा खतरा है। बेकाबू हो रहे प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के प्रति उत्साहित आइआइटी मंडी के शोधकर्ता प्लास्टिक को उपयोगी रसायनों में बदलने की विशेष विधियां विकसित कर रहे हैं। इस शोध का वित्तीयन शिक्षा मंत्रालय की

शिक्षा एवं शोध संवर्धन योजना स्पार्क के तहत किया गया था। शोध के निष्कर्ष हाल में जर्नल आफ एनवायर्नमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित किए गए। शोध का नेतृत्व डा प्रेम फेक्सिल सिरिल, प्रोफेसर, स्कूल आफ बेसिक साइंसेज, आइआइटी मंडी और डा अदिति हालदार, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ बेसिक साइंसेज, आइआईटी मंडी ने किया और इसमें उनकी पीएच.डी. विद्वान सुश्री रितुपर्णो गोगोई, सुश्री आस्था सिंह, सुश्री वेदश्री मुतम, सुश्री ललिता शर्मा, सुश्री काजल शर्मा ने सहयोग दिया। डा प्रेम फेक्सिल सिरिल, प्रोफेसर, स्कूल आफ बेसिक साइंसेज, आइआइटी मंडी ने कहा, 'प्लास्टिक से सही मायनों में छुटकारा पाने का आदर्श उपाय उसे उपयोगी रसायनों में बदलना है। प्लास्टिक से हाइड्रोजन बनाना विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि इस गैस को भविष्य का सबसे व्यावहारिक गैर-प्रदूषक इंधन माना जाता है। आइआइटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एक कैटलिस्ट विकसित किया है जो प्रकाश के संपर्क में प्लास्टिक को हाइड्रोजन और अन्य उपयोगी रसायनों में बदलने में सक्षम है। कैटलिस्ट कठिन या असंभव प्रतिक्रियाओं को अंजाम देने वाले पदार्थ हैं और प्रकाश से सक्रिय होने पर उन्हें फोटोकैटलिस्ट कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने एक संवाहक पालीमर - पॉलीपायरोल के माध्यम से फोटोकैटलिस्ट को नैनोपार्टिकल एक बाल के व्यास से सौ हजार गुना बारीक कण के रूप में आयरन आक्साइड के साथ संयोजन किया है। शोधकर्ताओं ने देखा कि पाइरोल के साथ आयरन आक्साइड नैनोकणों के संयोजन से एक सेमीकंडक्टर - सेमीकंडक्टर हेटरोजंक्शन बन गया जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश से प्रेरित फोटोकैटलिटिक गतिविधि नजर आई। फोटोकैटलिस्ट को सक्रिय करने के लिए आम तौर पर यूवी प्रकाश चाहिए और इसलिए विशेष बल्बों की आवश्यकता पड़ती है। आईआईटी मंडी का कैटलिस्ट सूरज की रोशनी में अपना काम कर सकता है।अपने शोध के बारे में डा प्रेम फेलिक्स सिरिल ने बताया, "हम ने सबसे पहले मिथाइल आरेंज पर हमारे कैटलिस्ट की प्रतिक्रिया देख कर इसकी फोटोकैटलिटिक गतिविधि सुनिश्चित की जो नारंगी से रंगहीन हो गया। यह दर्शाता है कि हमारा कैटलिस्ट किस सीमा तक इसे डिग्रेड करने में सक्षम था।"

बोरोसिल अब नए न्यूट्रीफ्रेश पीबी31 ब्लेंडर के साथ स्वास्थ्य की देखभाल करना हुआ और भी आसान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ भोजन और बेहतर रहन-सहन सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोरोना महामारी और वर्क फ्रॉम होम के चलते अधिकांश लोगों द्वारा मल्टी-टास्किंग और समय का कुशल प्रबंधन पूरे देश में देखा जाने लगा है। भारत के प्रमुख कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ब्रांड, बोरोसिल के नवीनतम प्रोडक्ट्स के लॉन्च ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के लिए चीजों को आसान बना दिया है, जिसमें मिलेनियल्स से लेकर प्रोफेशनल्स और गृहिणियाँ भी शामिल हैं।

बोरोसिल के नए, मेड इन इंडिया ब्लेंडर और ग्राइंडर, न्यूट्रीफ्रेश इँ31 को असेम्बल और उपयोग करना काफी आसान है और यह 400ॅ शुद्ध कॉपर मोटर, शक्तिशाली स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और 22,000 ॅइश से लैस है। यह असाधारण नुट्रिएंट एक्सट्रैक्शन पॉवर के साथ परेशानी मुक्त सफाई प्रदान करता है। न्यूट्रीफ्रेश इँ31 ब्लेंडर और मिक्सर एक आसान और स्वस्थ दिखने वाले लोगों के लिए आदर्श उपकरण है। यह उपकरण दो अटूट पॉली कार्बोनेट जार के साथ आता है। एक ब्लेंडिंग जार, जो सीधे तरल पदार्थ का उपभोग करने के लिए एक कंटेनर के रूप में कार्य करता है, और साथ ही सूखे मसालों को पीसने के लिए एक विशेष ब्लेड के साथ एक छोटा जार भी। दोनों ही जार बहु-उद्देशीय हैं। ब्लेंडिंग जार को चलते-फिरते आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है, जबकि दोनों जार के ढक्कनों का उपयोग सामान रखने के लिए किया जा सकता है। यदि आप घर का बना गरम मसाला या चटनी और स्प्रेड बनाना चाह रहे हों, तो यह मिक्सर ग्राइंडर आपकी रसोई में रखने के लिए एकदम सही साथी है। यह सभी सब्जियों, फलों और मसालों को सुचारू रूप से ब्लेंड करके हमारे काम को आसान बनाता है। हाई स्पीड ब्लेंडर आसानी से उपभोग करने के लिए फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से पीस देता है।

अगले एक साल में डिजिटल कौशल की जरूरत वाले कर्मचारियों की संख्या 2.73 करोड़ बढ़ेगी : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

अपने पेशे में डिजिटल कौशल की जरूरत वाले कर्मचारियों की संख्या अगले एक साल के दौरान 2.73 करोड़ बढ़ेगी। यह देश के कुल कार्यबाल का सात प्रतिशत बैठता है। अमेजन डॉट कॉम की कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज ने नई शोध रिपोर्ट के निष्कर्ष जारी किए हैं जिसके मुताबिक वैश्विक महामारी के दौरान डिजिटल कौशल प्रशिक्षण जरूरतें और भी स्पष्ट हो गई हैं। 'बदलते कार्यबल के लिए डिजिटल कौशल का निर्माण' शीर्षक की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल कर्मियों में से करीब 95 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें और डिजिटल कौशल की आवश्यकता है, जिससे कार्यस्थल पर काम के दौरान उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने की जानकारी मिल सके। इसमें कहा गया, "अगले एक साल के दौरान ऐसे भारतीय कर्मचारियों की संख्या 2.73 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है जिन्हें डिजिटल कौशल की आवश्यकता है, यह भारत के कार्यबल का सात प्रतिशत है।" इस सर्वेक्षण में, भारत में प्रौद्योगिकी और गैर-प्रौद्योगिकी भूमिकाओं में डिजिटल कौशल से युक्त 1,012 कर्मियों और 303 नियोक्ताओं से बात की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि और आधुनिक क्लाउड कंप्यूटिंग की जानकारी जैसे डिजिटल कौशल की आवश्यकता स्वास्थ्य से लेकर कृषि, फिनटेक से लेकर मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्रों तक में है। अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एडब्लयूएस इंडिया और दक्षिण एशिया (सार्वजनिक क्षेत्र) राहुल शर्मा ने कहा, "महामारी के दौरान सभी आकार के संगठनों ने अपनी डिजिटल रूपांतरण योजनाओं को तेज किया जिससे नियोक्ताओं और उनके कर्मियों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक कौशल प्रशिक्षण की जरूरत बढ़ गई।

कच्चे माल की कीमतों में उछाल की वजह से क्रेडाई-एनसीआर के सदस्य निर्माण 'रोकेंगे'

नयी दिल्ली। एजेंसी

रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई-एनसीआर ने सीमेंट और इस्पात जैसे कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण निर्माण कार्य रोकने की योजना बनाई है। क्रेडाई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि निर्माण लागत लगभग 500 रुपये प्रति वर्ग फुट बढ़ गई है और इससे आवास की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। उसने कहा कि कच्चे माल की लागत हाल में 30 से 40 प्रतिशत के भारित औसत से बढ़ी है, जबकि पिछले दो वर्षों में कुछ वस्तुओं की लागत में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। निकाय ने कहा, "लागत में अचानक और तेज वृद्धि ने रियल्टी परियोजनाओं के मार्जिन को कम कर दिया है और उन्हें अव्यावहारिक बना दिया है।" इसी के कारण क्रेडाई-एनसीआर के डेवलपर्स कच्चे माल की खरीद बंद करने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ऊंची लागत के कारण परियोजनाएं ठप हो जाएंगी।

एएससीआई ने एंडोर्सर ड्यू डिलिजेंस सर्विस शुरू की

एंडोर्सर्स को विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने से बचाया जा सके

सेवा 20 से अधिक विषयों के योग्य विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्रदान करेगी

इंदौर। एजेंसी

एंडोर्सर्स की मदद करने के लिए, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ऍएघ) कोड का और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) में दिये गए शर्तों का पालन करना जरूरी है। एएससीआई ने एंडोर्सर ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज़ की शुरुआत इन्डॉर्सर को विज्ञापनों में दिए जाने भ्रामक दावों से बचाने के लिए की है। एएससीआई की विशेषज्ञ सशुल्क परामर्श सेवा विज्ञापनों मे दिए जाने वाले तकनीकी दावे जो कि विज्ञापन का हिस्सा है, का मूल्यांकन करेगी। एएससीआई ने 20 से अधिक विषयों के विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया है, जिसमें विज्ञापन विनियमन और कानूनी, आयुर्वेद, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाजार अनुसंधान, पोषण, दंत चिकित्सा, उत्पाद निर्माण, वित्तीय सेवाएं आदि शामिल हैं। पैनल, उपभोक्ता और तकनीकी दृष्टिकोण से विज्ञापन में बताए गए दावों और बयानों का आकलन करेगा, जहां आवश्यक हो, दावे के पक्ष में सबूतों की जांच करेगी, और इस तरह एंडोर्सर को यथोचित सतर्कता रखने में मदद करेगी। एएससीआई को विज्ञापन, प्रोडक्शन के पहले या किसी स्तर को भेजे जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विज्ञापन बनने से पूर्व ही एंडोर्सर अपने आप उचित सावधानी रख सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, किसी भी उत्पाद या सेवा का एक अवधि के लिए झूठे या भ्रामक विज्ञापन करने वाले इन्डॉर्सर को जुर्माना लगाता है और एन्डॉर्स करने से भी रोक सकता है जिसे एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, अधिनियम ऐसे जुर्माने या निलंबन में छूट का भी प्रावधान रखता है, यदि इन्डॉर्सर ने उनके द्वारा किए गए किसी भी विज्ञापन में किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए उचित सतर्कता रखी हो। डफ एंड फेल्प्स की 'सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट' के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 20ङ की तुलना में, इंडिया में, विज्ञापनों में लगभग 50ङ अधिक मशहूर हस्तियों को दिखाया जाता है। यही रिपोर्ट यह भी बताती है कि इंडिया में 2020 के सबसे बड़े 20 एंडोर्सर्स की कुल ब्रांड वैल्यू लगभग 1बिलियन डॉलर है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर टीएएम ऐडएक्स (TAM AdEx) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में टीवी पर प्रसारित होने वाले 25% से अधिक विज्ञापन मशहूर हस्तियों द्वारा एन्डॉर्स किए गए थे, इनमें से 85ङ से अधिक फिल्मी सितारों द्वारा एन्डॉर्स थे। एएससीआई के अध्यक्ष सुभाष कामथ ने कहा एंडोर्सर्स, विशेष रूप से मशहूर हस्तियों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है और वे लाखों उपभोक्ताओं के विश्वास का प्रतीक होते हैं। इसलिए यह एक सीधे नैतिक ही नहीं बल्कि अब, कानूनी जिम्मेदारी भी है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए शुल्क वहन करते हैं कि उनके द्वारा भ्रामक विज्ञापनों का प्रतिनिधित्व तो नहीं किया जा रहा है। एएससीआई ने मशहूर हस्तियों द्वारा विज्ञापनों में प्रचार से पहले ध्यान में रखने की अपेक्षा की है, और अब कानूनी रूप से भी, उन्हें इस संबंध में उचित सतर्कता रखने की आवश्यकता है' एएससीआई द्वारा दी जाने वाली विज्ञापन सलाह सेवा के समान, एंडोर्सर ड्यू डिलिजेंस सर्विस गोपनीय और गैर-बाध्यकारी होगा और एंडोर्सर के नाम पर जारी किया जाएगा। एएससीआई की सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर ने कहा उत्पादों और उनके द्वारा किए गए दावों के बारे में इन्डॉर्सर हमेशा विशेषज्ञ नहीं होते हैं। कानून एंडोर्सर्स को उनके द्वारा ज्ञापित विज्ञापनों के लिए उत्तरदायी बनाता है, इसलिए एंडोर्सर के लिए उचित सतर्कता बहुत ही आवश्यक बन जाती है।

चालू वित्त वर्ष में सीमेंट उद्योग मात्रा के लिहाज से 18 से 20 प्रतिशत बढ़ेगा : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सीमेंट उद्योग में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में मात्रा के आधार पर 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और यह महामारी-पूर्व के स्तर पर पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इक्रा ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि कच्चे माल की कीमतों में उछाल के कारण चालू वित्त वर्ष में परिचालन मार्जिन 4.4 से 4.8 प्रतिशत घटकर 19.8 से 20.2 प्रतिशत रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया, ''सीमेंट उद्योग मात्रा के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 में 18 से 20 प्रतिशत बढ़कर 35.5 करोड़ टन पर पहुंच सकता है, जो कोविड महामारी-पूर्व के स्तर से छह प्रतिशत अधिक है।'' रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की मजबूत मांग और आधारभूत संरचना की गतिविधियों में तेजी से यह वृद्धि संभव है। इक्रा की एवीपी और क्षेत्र प्रमुख (कॉरपोरेट रेटिंग्स) अनुपमा रेड्डी ने कहा कि शुद्ध बिक्री प्राप्तियों में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले परिचालन मार्जिन (ओपीबीआईटीडीए) चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में प्रति टन 10 प्रतिशत घटकर 1,124 रुपये रह गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा कच्चे माल, बिजली और ईंधन, ढुलाई की कीमतों में उछाल के कारण हुआ है, जो सालाना आधार पर क्रमशः 12, 31 और पांच प्रतिशत बढ़े हैं।

Jio Platforms की सहायक कंपनी ने लॉन्च किया ड्रोन ऑपरेशन प्लेटफॉर्म

खेती-किसानी में ला सकता है बड़े बदलाव

नई दिल्ली। एजेंसी

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की सब्सिडियरी और भारत में ड्रोन बनाने वाली कंपनी एस्टेरिया एयरोस्पेस ने एंड-टू-एंड ड्रोन ऑपरेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम स्काईडेक है। यह एक क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कृषि, सर्वेक्षण, निगरानी, औद्योगिक निरीक्षण व सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए एंड-टू-एंड ड्रोन सॉल्यूशंस मुहैया कराता है। स्काईडेक दरअसल एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ड्रोन की उड़ानों के विभिन्न आयामों और उनसे जुड़े डेटा को दर्ज करता है। साथ ही यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से विकसित किये गए एक डेशबोर्ड पर इस डेटा को प्रदर्शित करता है। ड्रोन डेटा की प्रोसेसिंग, डेटा के विजुअलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा के विशलेषण की सुविधा भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा ड्रोन की उड़ानों को शेड्यूल करने से लेकर ड्रोन बेड़े के प्रबंधन का काम भी इस सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है।

ड्रोन की मांग में हुई है वृद्धि

एस्टेरिया एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और निदेशक नील मेहता ने कहा, 'ड्रोन संचालन के लिए नियमों को सरल बनाने और सरकार द्वारा ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा देने से इसकी मांग में वृद्धि हुई है। एस्टेरिया पहले से ही भारत में अग्रणी ड्रोन निर्माताओं में से एक है। स्काईडेक के लॉन्च के साथ ही हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचालन सॉल्यूशंस जैसी तमाम सुविधाएं, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए मुहैया करा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में भी बड़े बदलाव ला सकता है स्काईडेक

स्काईडेक ड्रोन के उपयोग को सरल बनाने, उड़ान संबंधित डेटा दर्ज करने और एकत्रित डिजिटल डेटा को बिजनेस आइडिया में बदलने में मदद करता है।' स्काईडेक का एंड टू एंड सॉल्युशन कृषि क्षेत्र में भी बड़े बदलाव ला सकता है। इसका उपयोग फसल के लक्षणों को सटीक रूप से मापने, कीड़े, खाद, पानी आदि की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। निर्माण और खनन उद्योगों में स्काईडेक द्वारा ड्रोन-बेस्ट डेटा का उपयोग सटीक इन्वेंट्री रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए और साइट सर्वेक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मिलेगी मदद

तेल व गैस, दूरसंचार और बिजली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में स्काईडेक रखरखाव, खतरों की पहचान करने और बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग हो सकता है। साथ ही संपत्तियों का डिजिटलीकरण और निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग हो सकता है। स्काईडेक विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे स्वमित्व योजना, स्मार्ट सिटीज, एग्रीस्टैक और अन्य विकास परियोजनाओं में ड्रोन के बेड़े के सफल कार्यान्वयन में भी मदद कर सकता है।

News यू केन USE

समय पर उड़ानों के संचालन में इंडिगो अव्वल, गोफर्स्ट दूसरे स्थान पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो फरवरी माह में समय पर उड़ानों के संचालन (ओटीपी) के मामले में देश के चार प्रमुख हवाईअड्डों पर सबसे आगे रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। डीजीसीए के अनुसार, इस दौरान कंपनी की समय पर उड़ानों की संख्या 95.4 प्रतिशत रही। वहीं 94.1 प्रतिशत के ओटीपी के साथ गोफर्स्ट दूसरे स्थान पर रही। डीजीसीए ने सोमवार को जारी आंकड़ों में कहा कि बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई हवाईअड्डों पर इंडिगो का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। डीजीसीए के अनुसार, जनवरी, 2022 में 94.5 प्रतिशत के साथ गोफर्स्ट का ओटीपी इन चार हवाईअड्डों पर सबसे अच्छा रहा था। इस दौरान इंडिगो 93.9 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर थी। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, ''चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद समय पर उड़ानों के मामले सबसे अच्छे प्रदर्शन को लेकर हम खुश हैं। हम ओटीपी को फरवरी 2022 में 95.4 प्रतिशत पर पहुंचाने में सफल रहे हैं, जो 2021 में वार्षिक मासिक औसत के आधार पर 93.5 प्रतिशत था।'' इसके अलावा फरवरी, 2022 में विस्तारा, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, एयरएशिया इंडिया और अलायंस एयर का ओटीपी क्रमशः 90.9 प्रतिशत, 90.9 प्रतिशत, 89.8 प्रतिशत, 88.5 प्रतिशत और 88.5 प्रतिशत रहा।

सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकॉर्बन्स के निर्यात पर 'अंकुश' लगाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकॉर्बन्स के निर्यात पर अंकुश लगा दिया है। यह कदम घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस रसायन का इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग क्षेत्र में होता है।अब निर्यातकों को हाइड्रोफ्लोरोकॉर्बन्स (एचएफसी) के निर्यात के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा, ''हाइड्रोफ्लोरोकॉर्बन्स के लिए निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से मुक्त से अंकुश की श्रेणी में संशोधित किया गया है। इसके निर्यात के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की जरूरत होगी।'' यह कदम इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन (व्हाइट गुड्स) के लिए 6,238 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की है। पीएलआई योजना का उद्देश्य एसी और एलईडी लाइट के लिए कलपुर्जों तथा उप-असेंबली के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। इससे पहले इसी महीने सरकार ने एचएफसी के आयात पर भी इसी तरह के अंकुश लगाए थे।

'स्ट्रीट फर्नीचर' के जरिये दूरसंचार ढांचा लगाने को पायलट अध्ययन शुरू

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'स्ट्रीट फर्नीचर' के इस्तेमाल के जरिये दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अगली पीढ़ी का दूरसंचार ढांचा लगाने को पायलट आधार पर अध्ययन शुरू किया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय हवाईअड्डों पर मौजूदा स्ट्रीट फर्नीचर मसलन यातायात सिग्नल, साइनेज, लैंप पोस्ट, लाइट पोल और बिलबोर्ड का इस्तेमाल कर 'स्मॉल सेल' लगाया जा सकता है। स्ट्रीट फर्नीचर से तात्पर्य सड़कों और गलियों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपकरणों से है। नियामक ने मंगलवार को बयान में कहा, ''अगली पीढ़ी के नेटवर्क को तेजी से लागू करने को डिजिटल ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ट्राई ने दिल्ली के जीएमआर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पायलट अध्ययन शुरू किया है।''

शीतला पूजा पर्व:बच्चों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के साथ ही घर में सुख-समृद्धि के लिए महिलाएं करती हैं ये व्रत

शीतला माता का पर्व चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। शीतला माता अपने साधकों के तन-मन को शीतल करने और हर तरह की परेशानी खत्म करने वाली मानी गई हैं। शीतला माता की पूजा और व्रत सप्तमी या अष्टमी को किया जाता है। इसे बसौड़ा या बसौरा भी कहा जाता है। इस साल ये पर्व 24 और 25 मार्च को मनाया जाएगा।

पौराणिक कथा और महत्व

एक बार की बात है, प्रताप नगर में गांववासी शीतला माता की पूजा-अर्चना कर रहे थे और पूजा के दौरान गांव वालों ने गर्म नैवेद्य माता शीतला को चढ़ाया। जिससे देवी का मुंह जल गया। जिससे गांव में आग लग गई। लेकिन एक बुढ़िया का घर बचा गया था।

गांव वालों ने बुढ़िया से घर न जलने की वजह पूछी तो बताया कि उसने माता शीतला को ठंडा प्रसाद खिलाया था और कहा कि मैंने रात को ही प्रसाद बनाकर ठंडा बासी प्रसाद माता को खिलाया। जिससे देवी ने प्रसन्न होकर मेरे घर को जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने अगले पक्ष में सप्तमी/अष्टमी के दिन उन्हें बासी प्रसाद खिलाकर माता शीतला का बसौड़ा पूजन किया।

सुख-समृद्धि के लिए व्रत

हिन्दू धर्म के अनुसार सप्तमी और अष्टमी तिथि पर महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की सलामती के लिए और घर में सुख, शांति के लिए बासौड़ा बनाकर माता शीतला को पूजती है। माता शीतला को बासौड़ा में कढ़ी-चावल, चने की दाल, हलवा, बिना नमक की पूड़ी चढ़ावे के एक दिन पहले ही रात में बना लेते हैं। अगले दिन ये बासी प्रसाद देवी को चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद महिलाएं अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करती हैं।

27 मार्च से इन राशि वालों का जगेगा भाग्य

देवगुरु बृहस्पति को शुभता, संपत्ति, धन, वैभव व वैवाहिक जीवन आदि का कारक माना जाता है। 32 दिनों के बाद गुरु ग्रह उदित होने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, गुरु यानी बृहस्पति ग्रह 23 फरवरी को अस्त हुए थे। 32 दिनों के बाद गुरु अस्त होने के बाद अब 27 मार्च 2022 को उदित होंगे। गुरु अस्त होने से इन 3 राशि वालों को होगा महालाभ-

कन्या- गुरु के उदय होने के आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को तरक्की मिल सकती है। इस दौरान नौकरी में भी नए अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

तुला- तुला राशि वालों को धन के मामले में लाभ हो सकता है। लंबे समय से रूके काम पूरे हो सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार रहें। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। सेहत के मामले में इस दौरान सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आलस से बचें।

मकर- मकर राशि वालों के लिए गुरु की यह स्थिति विशेष लाभ प्रदान करने जा रही है। इस दौरान पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। किसी रोग से राहत मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। वाणी की मधुरता बनाए रखें। जीवनसाथी की सलाह अवश्य ध्यान रखें। विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं।

करियर में सफलता पाने अपनाएं इनमें से कोई एक उपाय

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

हर व्यक्ति चाहता है कि उसे काम में सफलता हासिल हो। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। अगर आपको भी मेहनत का उचित फल नहीं नहीं मिल पा रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं वास्तु टिप्स जिससे आपको लाभ मिलेगा। वास्तु शास्त्र में घर, ऑफिस और करियर आदि के लिए कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जानें करियर में सफलता पाने के वास्तु टिप्स-

सफाई का रखें ध्यान- ऑफिस या घर पर जिस जगह आप बैठते हैं, वहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने डेस्क पर बेवजह का सामान फैला कर न रखें। वास्तु में इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि डेस्क पर सामान फैला कर रखने से तरक्की में बाधा आती है।

रोशनी वाली जगह- अगर आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ऑफिस का काम जिस जगह भी बैठकर करते हैं वहां भरपूर रोशनी आए। सूर्य की किरणों को वास्तु में बेहद शुभ माना जाता है।

सीट पर रखें ये चीजें- करियर में सफलता पाने के लिए सीट पर क्रिस्टल रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। डेस्क पर बांस का पौधा रखना भी लाभकारी माना जाता है।

इस दिशा में रखें मुख- वास्तु शास्त्र के अनुसार, आपकी सीट उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। आपका मुंह उत्तर-पूर्व दिशा की ओर होने से आपको लाभ मिलता है।

इस रंग के न पहनें कपड़े- वास्तु शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना गया है। काला रंग नकारात्मकता को दर्शाता है। ऐसे में करियर में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए काले रंग के कपड़े ना पहनें।

केवल 15 दिन के अंतर में लगेंगे साल के दो बड़े ग्रहण

ग्रहण की घटना का ज्योतिषीय व वैज्ञानिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगने हैं। जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण व दो चंद्रग्रहण शामिल हैं। हिंदू धर्म में सूर्य व चंद्र ग्रहण दोनों का बराबर महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 30 अप्रैल 2022 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। वहीं, सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा। इन दोनों ग्रहण का मानव जीवन पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जानें साल 2022 में लगने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव-

1. मेष- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल का पहला सूर्यग्रहण आपकी राशि में ही लगेगा। 15 दिन के अंतर में लगने वाले दोनों ग्रहण का आप पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। आपको कार्यस्थल पर तरक्की मिलने केयोग बनेंगे। व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है। इस दौरान आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत अच्छा विचार हो सकता है।

2. सिंह- सिंह राशि वालों पर चंद्र व सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। सिंह राशि वालों की इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। पदोन्नति की संभावना है। आय के साधन बढ़ने के साथ आप निवेश पर भी ध्यान देंगे। सिंह राशि वालों के लिए यात्रा केयोग बनेंगे। यह यात्रा आपको आर्थिक तरक्की दिला सकती है।

3. धनु- धनु राशि वालों पर दोनों ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। सूर्य व चंद्र ग्रहण के दौरान आपके अटके काम पूरे होंगे।

कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण

साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022, सोमवार को सुबह 08 बजकर 59 मिनट पर लगेगा, जो कि 10 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगा। भारत मे चंद्र ग्रहण आंशिक होने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा।

माणिक धारण करने से निखर जाती है आपके अंदर की प्रतिभा

ज्योतिष की रत्न शाखा में माणिक को सूर्य का रत्न माना गया है जिसमें सूर्य के गुण विद्यमान होते हैं और अधिकांशतः कुंडली में सूर्य के पीड़ित या कमजोर होने पर माणिक धारण करने की सलाह दी जाती है। माणिक गहरे गुलाबी या महरून रंग की आभा लिए होता है। माणिक एक बहुत ही ऊर्जावान रत्न होता है जिसे धारण करने से कुंडली में स्थित सूर्य को बल तो प्रदान होता ही है, साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। माणिक धारण करने से व्यक्ति की इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाते हैं। आंतरिक सकारात्मक शक्ति और इम्युनिटी बढ़ती है। सामाजिक प्रतिष्ठा, यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। माणिक धारण करने से व्यक्ति में प्रतिनिधित्व करने की शक्ति आती है और उसकी प्रबंधन कुशलता भी बढ़ जाती है। परिस्थितियों को मैनेज करने में वह व्यक्ति सक्षम होता है। माणिक धारण करने पर व्यक्ति के अंदर दबी हुई प्रतिभाएं उदित हो जाती हैं और वह भय मुक्त होकर अपनी प्रतिभा का अच्छे से प्रदर्शन कर पाता है। आंखों से जुड़ी समस्याएं, दृष्टि की समस्या, हृदय रोग,बाल झड़ने और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में भी माणिक धारण करने से सकारात्मक परिणाम मिलता है।

जिन लोगों में भय, निराशा, आत्मविश्वास की कमी या दबे हुए व्यक्तित्व की समस्या होती है उनके लिए माणिक धारण बहुत ही सकारात्मक परिणाम लाता है। लेकिन माणिक केवल उन्हीं व्यक्तियों को पहनना चाहिए जिनके लिए सूर्य शुभकारक ग्रह है। माणिक सकारात्मक रत्न है। इस रत्न को धारण करने से पहले अच्छे ज्योतिषी से अवश्य चर्चा कर लें। सामान्यतः मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न के लिए माणिक धारण करना शुभ है। कर्क लग्न के लिए यह मध्यम है। मीन, मकर और कन्या लग्न के लिए माणिक धारण करना हानिकारक होता है।

ऐसे धारण करें माणिक

माणिक को तांबे या सोने की अंगूठी में बनवाकर सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को धारण करना चाहिए। इसके अलावा लॉकेट के रूप में लाल धागे के साथ गले में भी धारण कर सकते हैं। माणिक धारण करने से पूर्व उसे गाय के दूध या गंगाजल से अभिषेक करके धूप-दीप जलाकर सूर्य मंत्र का जाप करके पूर्वाभिमुख होकर माणिक धारण करना चाहिए। माणिक धारण करने के लिए 'ऊं घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र की एक से तीन माला अवश्य करें।

अदाणी पोर्ट्स का कार्गो वॉल्यूम बढ़कर 30 करोड़ मीट्रिक टन हुआ

2025 तक 500 एमएमटी हासिल करने की राह पर भारत की सबसे बड़ी परिवहन कंपनी

अहमदाबाद। एजेंसी

भारत में सबसे बड़ी एकीकृत परिवहन कंपनी और विभिन्न व्यवसायों में सक्रिय अदाणीग्रुप कीकंपनी, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ('एपीएसईज़ेड'), ने वर्ष के अंत (मार्च 2022)से पहले ही 300 एमएमटी कार्गो की हैंडलिंग करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दो दशक पहले ही परिचालन शुरू करने वाले एपीएसईज़ेड ने अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। एपीएसईज़ेडअखिल भारतीय कार्गो वॉल्यूम वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हैऔर इसकी बाजार हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। एपीएसईज़ेड के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री करण अदाणी ने बताया कि 'हमारे कार्गो वॉल्यूम में हुई तेज वृद्धि अपनी रणनीति को कार्यान्वित करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है।हमारी एकीकृत लॉजिस्टिक्स क्षमताओं के साथ जुड़ा हुआ, भारतीय समुद्र तट पर बंदरगाहों का हमारा नेटवर्क

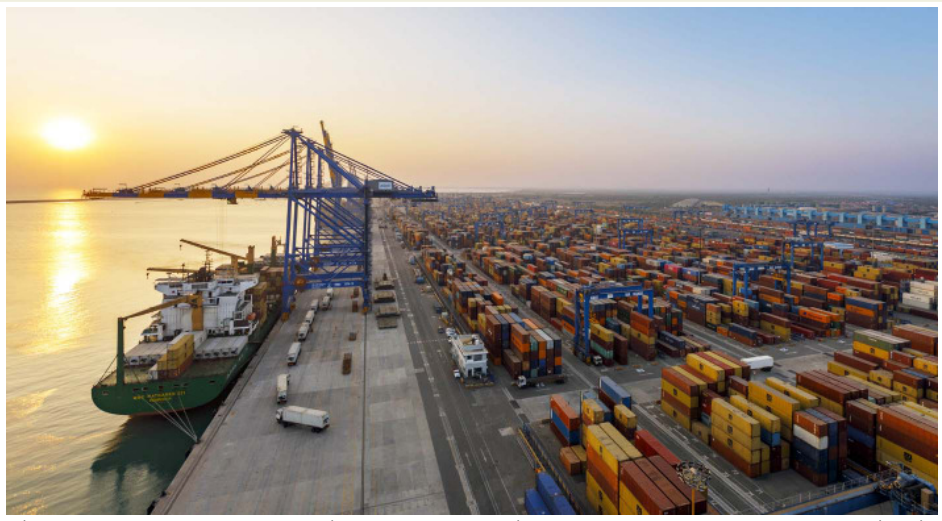

प्रौद्योगिकी-सक्षम डिजिटल परिचालन पर ध्यान केंद्रित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने ग्राहकों और भागीदारों (जिसमें वैश्विक शिपिंग लाइनें शामिल हैं) के साथ गहरे संबंध बनाए हैं, और ये सब मिलकर एपीएसईज़ेड को एक संपूर्ण एकीकृत बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं जोएक-दूसरे कीप्रगति में योगदान देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्षमताओं को देखते हुए हमारे विकास में आई तेजी जारी रहेगी। हमारी क्षमताएं अब अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं और बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सहायक हैं।'

श्री अदाणी ने कहा कि 'यह उपलब्धि वैश्विक बाजार और भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण हो रहे तेज परिवर्तनों के अनुकूल होने के साथ ही एपीएसईज़ेडकी क्षमता को भी रेखांकित करती है और एपीएसईज़ेड के सस्टेनेबल विकास में मदद करती है। हमारे विकास को आगे बढ़ाने वाली अपनी समर्पित टीमों और व्यावहारिक तौर पर इसे साकार करने वाले हमारे महान कार्यबल मैं धन्यवाद देता हूं। हम 2025 तक 500 एमएमटी के अपने लक्ष्य तक पहुंचने और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह कंपनी के रूप में उभरने के प्रति आश्वस्त हैं।' एपीएसईज़ेडकार्गो वॉल्यूम बढ़ाने में लगने वाले समय में लगातार तेजी ला रहा है। जहां इसे प्रति वर्ष 100 एमएमटी (अपने पोर्टफोलियो में पांच पोर्ट के साथ) हासिल करने में 14वर्ष लगे, वहीं एपीएसईज़ेड ने अगले पांच वर्षों में इसे दोगुना करते हुए200 एमएमटी वार्षिक (अपने पोर्टफोलियो में नौ पोर्ट के साथ) कर दिया। अबअपने पोर्टफोलियो में 12 पोर्ट के साथ, एपीएसईज़ेड की प्रति वर्ष 300 एमएमटी हैंडलिंग करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि सिर्फ तीन वर्षों में हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि 200 एमएमटी से 300 एमएमटी तक की तीन वर्ष की यात्रा में महामारी के कारण पैदा हुई वैश्विक आर्थिक मंदी के दो वर्ष भी शामिल हैं।

अपने व्यवसाय परिचालन में तेजी लाने के साथ-साथ, एपीएसईज़ेड ने सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को भी अच्छी तरह से पूरा किया है। ऊर्जा और उत्सर्जन की तीव्रता मं 2016 के स्तर से लगभग 30इ की कमी आई है। रबर टायर्ड गैन्ट्री क्रेन्स (आरटीजी) का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है, और क्वे क्रेन्स और मोबाइल हार्बर क्रेन्स का विद्युतीकरण प्रगति पर है, जिसको वर्ष 2023तक पूरा करने का लक्ष्य है। डीजल आधारित इंटरनल ट्रांसफर व्हीकल्स (आईटीवी) को इलेक्ट्रिक आईटीवी से बदला जा रहा है। 100 इलेक्ट्रिक आईटीवी का पहला बैच 2022 के मध्य में आने की संभावना है और उम्मीद है कि आईटीवी की कुल संख्या 2023 में 400 को पार कर जाएगी। एक अन्य ग्रीन पोर्ट पहल के तहत ईंधन के रूप में एलएनजी का उपयोग करने वाले जहाजों के लिए पोर्ट ड्यूज़, पाइलोटेज और बर्थ किराया शुल्क में 50इ की छूट है। पहले से चल रहे वनीकरण और कई अन्य हरित उपायों के साथ, एपीएसईज़ेड 2025 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है।

भारत मिस्र को गेहूं निर्यात करने के लिए कर रहा है निर्णायक बातचीत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए अंतिम दौर की बातचीत कर रहा है, जबकि चीन, तुर्की और ईरान जैसे देशों के साथ गेहूं के निर्यात के लिए बातचीत चल रही है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान बढ़कर 1.74 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो इससे पिछले साल की समान अवधि में 34.02 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। मंत्रालय ने कहा कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने हाल में उन देशों को निर्यात बढ़ाने के संबंध में प्रमुख हितधारकों की एक बैठक आयोजित की है, जिन्हें रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के चलते बड़ी खेप भेजने की क्षमता है। बैठक में रेलवे ने अतिरिक्त गेहूं परिवहन की किसी भी तत्काल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बंदरगाह अधिकारियों से गेहूं के निर्यात के लिए समर्पित टर्मिनलों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है।

भारत से गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों में होता है, जिसमें बांग्लादेश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा देश ने यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे नए गेहूं के बाजारों में प्रवेश किया है। एपीडा के अध्यक्ष एम अंगमुथु ने कहा, 'हम राज्य सरकारों और निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों, ट्रांसपोर्टरों जैसे हितधारकों के सहयोग से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य श्रृंखला के निर्माण पर जोर दे रहे हैं।' वैश्विक स्तर पर गेहूं निर्यात में भारत की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है, हालांकि इसका हिस्सा 2016 में 0.14 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 0.54 प्रतिशत हो गया है।

भारत बनेगा ई-व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग का बड़ा हब

इस जापानी कंपनी ने किया 1.26 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान

नयी दिल्ली। एजेंसी

वह दिन दूर नहीं, जबकि भारत भी ई-व्हीकल के मैन्यूफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा। जापान की दिग्गज व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारत में 1.26 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। इस निवेश से यहां इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी।

गुजरात में लगेगी फैक्ट्री

जापान के दैनिक समाचार पत्र 'निक्केई' की एक खबर में इस बारे में बताया गया है। इस खबर के मुताबिक गुजरात में सुजुकी की ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के पास ही बैटरी यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस नई यूनिट पर कुल लगभग 150 बिलियन येन (1.26 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश का अनुमान है। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

शिखर वार्ता के दौरान घोषित निवेश का हिस्सा

खबर में कहा गया है कि यह निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान घोषित जापान के कुल निवेश में शामिल है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शनिवार को भारत आ गए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को लंबे समय तक सरकारी समर्थन की जरूरत: संसदीय समिति

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

संसद की एक समिति ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माताओं को दीर्घावधि के लिए सरकारी समर्थन देने का सुझाव दिया। समिति ने कहा कि जबतक यह क्षेत्र टिकाऊ , सस्ता और आम आदमी की पहुंच में नहीं आता है, तबतक ईवी विनिर्माताओं को सरकारी समर्थन की जरूरत होगी।

उद्योग पर संसद की स्थायी समिति ने फेम-दो (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से विनिर्माण और उसे अपनाना) योजना के तहत निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में धीमी प्रगति को लेकर भी चिंता जतायी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय को उद्योग, अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों के साथ मिलकर शोध प्रयासों के जरिये प्रौद्योगिकीय समाधान की दिशा में काम कर व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

समिति के अनुसार, मंत्रालय को ईवी के उत्पादन, बिक्री और प्रोत्साहन के प्रसार को लेकर रूपरेखा पर काम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''समिति का विचार है कि विनिर्माताओं को लंबे समय तक सरकार से समर्थन की जरूरत है। यानी यह समर्थन तबतक जरूरी है जबतक ईवी बाजार टिकाऊ, अधिक किफायती और आम आदमी की पहुंच में नहीं आता है।'' समिति ने मध्यम से लेकर दीर्घावधि के लिये पारदर्शी नियामकीय रूपरेखा की सिफारिश की है। इसमें उद्योग के लिये नियमन के मामले में अलग-अलग समयसीमा के साथ ब्योरा होना चाहिए ताकि वे निवेश, प्रौद्योगिकी और उत्पादक विकास को लेकर बेहतर तरीके से योजना बना सकें। इसके अलावा प्रौद्योगिकी की लागत में कमी लाने के लिये समिति ने वाहनों के कलपुर्जों के स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।

श्रीलंका में सेना के साये में बिक रहा पेट्रोल

कोलंबो। एजेंसी

आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में सेना के साये में पेट्रोल-डीजल बिक रहा है. तेल की कमी के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसे में भीड़ कोई हिंसक कदम न उठाए, इसे ध्यान में रखते हुए सेना के जवानों को यहां तैनात किया गया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार काफी घट गया है। इस वजह से पेट्रोल-डीजल का आयात मुश्किल हो रहा है। महंगाई ने भी यहां सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

भारत-चीन से मांगी आर्थिक मदद

श्रीलंका में अनाज, चीनी, सब्जियों से लेकर दवाओं की भी भारी कमी हो गई है। महंगाई की वजह से लोगों का खर्चा चार गुना तक बढ़ गया है। लेकिन उनकी आमदनी उतनी ही है। सरकार को इस वक्त अनाज, तेल और दवाओं की खरीद के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। भारत ने एक अरब डॉलर का कर्ज देने का वादा किया है और चीन भी श्रीलंका को ढाई अरब डॉलर का कर्ज दे सकता है। बता दें कि 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका सबसे भयावह आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

सेना की तैनाती पर ये बोले ऊर्जा मंत्री

श्रीलंका में पेट्रोल-डीजल के लिए लंबी लाइनों को देखते हुए मंगलवार को सरकारी पेट्रोल पंपों पर सैनिकों को तैनात कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ऊर्जा मंत्री गामिनी लुकोगे ने का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो इसलिए सेना को यहां तैनात करने का फैसला लिया गया है। लोग बड़े कैन में पेट्रोल ले जाकर बिजनेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पेट्रोल सबको मिले'।

रसोई गैस के लिए भी लंबी लाइनें

केवल पेट्रोल ही नहीं रसोई गैस के लिए भी लंबी लाइनें लग रही हैं। पेट्रोल और केरोसिन के लिए लाइनों में खड़े चार लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से तीन बुजुर्ग थे। एक शख्स की मौत लाइन में लगे लोगों के बीच झगड़े के दौरान चाकूबाजी की वजह से हुई थी। इसके अलावा, श्रीलंका को भारी बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। मार्च की शुरुआत में सरकार ने अधिकतम साढ़े सात घंटे तक की बिजली कटौती का ऐलान किया था।

ऐसे बिगड़ती गई आर्थिक सेहत

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक की ओर से फरवरी में जारी आंकड़ों के अनुसार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 में 24.8 फीसदी घट कर 2.36 अरब डॉलर रह गया था। रूस-यूक्रेन में छिड़ी जंग से भी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत बदतर हो सकती है। क्योंकि रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। अब सवाल यहां ये उठता है कि आखिर श्रीलंका इस स्थिति में पहुंचा कैसे? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी है करीब दस फीसदी है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका में पर्यटकों का आना बिल्कुल बंद हो गया और देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता गया। इस वजह से कनाडा जैसे कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका में निवेश बंद कर दिया है।

सरकार के गलत फैसले भी दोषी

कोविड से हुए नुकसान के साथ ही श्रीलंका की सरकार ने कुछ ऐसी गलतियां की, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई। उदाहरण के तौर पर, 2019 में नवनिर्वाचित सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। देश में केमिकल फर्टिलाइजर से खेती बंद करने के आदेश का भी घातक असर हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे फसल उत्पादन में खासी गिरावट आई है। इसके अलावा, श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति की वजह इस पर बढ़ता कर्ज भी है। अकेले चीन से ही श्रीलंका ने 5 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। भारत और जापान का भी इस पर काफी कर्ज है।

इस साल चुकाना है इतना कर्ज

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में श्रीलंका को सात अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। मौजूदा हालात को देखते हुए श्रीलंका के डिफॉल्ट होने का खतरा काफी ज्यादा है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (घ्ष्इ) से भी बेलआउट पैकेज की गुहार लगाई है। यदि उसकी ये गुहार पूरी नहीं होती, स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक रिपोर्ट बताती है कि एशियाई देशों में सबसे ज्यादा महंगाई श्रीलंका में बढ़ी है। फरवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2022 में खुदरा महंगाई 15.1 फीसदी बढ़ गई।

एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 'एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स फंड' लॉन्च किया

मुंबई। एजेंसी

एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो भारत में अग्रणी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक है, ने आज एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स फंड (निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एकओपन एंडेड इंडेक्स फंड) लॉन्च करने की घोषणा की। जिनेश गोपानी, हेड-इक्विटी द्वारा प्रबंधित, यह फंड निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स टीआरआई को ट्रैक करेगा। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10 मार्च 2022 को खुलेगा और 21 मार्च 2022 को बंद होगा। न्यूनतम आवेदन राशि 5,000 रु. है और उसके बाद निवेशक 1 रु. के गुणकों में निवेश कर सकते हैं।

निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स

भारत निरपेक्ष विकास के चरण में है जहां विभिन्न उभरती कंपनियां विकास की संभावनाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा, ये कंपनियां लचीली प्रकृति की हैं, जिससे निवेशक के लिए सही मिडकैप का चयन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। निफ्टी

मिडकैप 50 इंडेक्स में निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स से पूर्ण बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 50 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें उन स्टॉक्स को वरीयता दी गयी है जिन पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर उपलब्ध हैं। सूचकांक को पिछले छह महीनों के औसत डेटा का उपयोग करके अर्ध - वार्षिक आधार (मार्च और सितंबर) पर पुनः संतुलित किया जाता है।

एक्सिस एएमसी के एमडीऔर सीईओ, श्री चंद्रेश निगम ने कहा, 'व्यापक बाजार में, मिडकैप्स ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे वो दीर्घकालिक धन सृजन के लिए आदर्श बन गये हैं। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु के साथ, वे एक अनुकूल जोखिम - लाभ कोशियंट भी प्रदान करते हैं। एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इंडेक्स फंड की शुरूआत, निवेशकों को गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करने के हमारे विश्वास के अनुरूप है जो उनकी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार है। हमारा मानना है कि यह पैसिव पेशकशों के हमारे पोर्टफोलियो में एक उल्लेखनीय जुड़ाव होगा।'

विदेशी मुद्रा भंडार 9.65 अरब डॉलर घटकर 622.27 अरब डॉलर पर

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 मार्च को समाप्त सप्ताह में 9.646 अरब डॉलर घटकर 622.275 अरब डॉलर पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पूर्व चार मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 39.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 631.92 अरब डॉलर हो गया था। इससे पूर्व तीन सितंबर, 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशीमुद्रा भंडार 642.453 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचा था। आरबीआई के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के घटने की वजह से आई जो कुल मुद्राभंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आंकड़ों के अनुसार 11 फरवरी को समाप्त सप्ताह में एफसीए 11.108 अरब डॉलर घटकर 554.359 अरब डॉलर रह गया। डॉलर में अभिव्यक्त विदेशी मुद्रा भंडार में रखे जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्रा के मूल्यवृद्धि अथवा मूल्यह्रास के प्रभावों को शामिल किया जाता है। आलोच्य सप्ताह में स्वर्ण भंडार 1.522 अरब डॉलर बढ़कर 43.842 अरब डॉलर हो गया। समीक्षाधीन सप्ताह में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास जमा विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 5.3 करोड़ डॉलर घटकर 18.928 अरब डॉलर रह गया। आईएमएफ में रखे देश का मुद्रा भंडार 70 लाख डॉलर घटकर 5.146 अरब डॉलर रह गया।

बड़ी उपलब्धि : भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर का किया निर्यात

तय समय से पहले ही हासिल कर लिया लक्ष्य

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 की मार और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने 400 अरब डॉलर के माल निर्यात के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भारत सरकार की ओर से तय की गई अवधि से 9 दिन पहले ही इस लक्ष्य को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने हर दिन औसतन 1 अरब डॉलर का निर्यात किया। वहीं, महीने के हिसाब से देखें तो हर महीने 33 अरब डॉलर वस्तुओं का निर्यात किया गया।

'आत्मनिर्भर भारत यात्रा में अहम मील का पत्थर'

भारत की इस शानदार उपलब्धि की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, 'भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, निर्माताओं व निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ' ट्वीट में पीएम मोदी ने बताया है कि सरकार ने तय समय सीमा से 9 दिन पहले ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया है।

आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा भी बढ़ा

भारत का आयात भी कच्चे तेल और सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण 36 फीसदी बढ़ गया है। इसी कारण जनवरी में 17.4 अरब डॉलर का व्यापार घाटा फरवरी में 20.9 अरब डॉलर हो गया। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण

कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद फरवरी में भारत की सेवाएं और विनिर्माण गतिविधि स्थिर रहीं। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा संकलित किए गए सभी आठ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ने स्थिरता का संकेत दिया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।